Australian Government

Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman

MEDIA RELEASE

अगस्त 2023

लोकपाल हिंदी भाषी व्यवसायियों से खरीद सलाह देने का आह्वान कर रहे हैं

ऑस्ट्रेलियाई लघु व्यवसाय एवं पारिवारिक उद्यम लोकपाल (Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman) ब्रूस बिल्सन ने हिंदी भाषी छोटे व्यवसायों के मालिकों से ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ व्यापार करने की प्रणाली में सुधारों के बारे में उनकी सलाह देने का आह्वान किया है।

श्री बिल्सन ने छोटे व्यवसायों पर राष्ट्रमंडल खरीद नियमों में सुधारों के प्रभाव की खोजबीन करने के लिए एक जांच आरंभ की है व मुद्दे पत्र जारी किया है और वे सार्वजनिक प्रस्तुतियों के लिए आह्वान कर रहे हैं।

"तीन में से एक छोटा व्यवसाय ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाता है जो विदेशों से ऑस्ट्रेलिया आए हैं और ये व्यवसाय समुदाय की जीवंतता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवनशक्ति में मूल्यवान योगदान देते हैं," श्री बिल्सन ने कहा।

"प्रवासियों ने व्यवसाय कैसे निर्मित और विकसित किए हैं, इसकी कई कहानियाँ प्रेरणादायक हैं और मैं वास्तव में इस बारे में उनके विचार सुनना चाहूंगा कि हम खरीद प्रणाली में सुधार कैसे कर सकते हैं।"

वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार और इसके निकायों ने 92,303 अनुबंध जारी किए, जिनका संयुक्त मूल्य $80.8 बिलियन है।

अनुमानित रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को संख्या के हिसाब से 55% या मूल्य के हिसाब से 31% अनुबंध दिए गए थे, जिनकी कीमत लगभग $25 बिलियन थी। केवल छोटे व्यवसायों के लिए ही $8.5 बिलियन मूल्य के काम (या मूल्य के अनुसार सभी अनुबंधों के 10.5% अंश) का हिसाब लगाया गया।

"एसएमई (SMEs) को सरकारी काम के लिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम बनाने से बेहतर मूल्य वितरित करने में सहायता मिलती है, नवाचार को समर्थन मिलता है एवं और अधिक सशक्त ऑस्ट्रेलिया-आधारित क्षमता उद्वेलित होती है – ये सभी करदाताओं और हमारे देश के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण लाभ हैं," श्री बिल्सन ने कहा।

"कई छोटे व्यवसायों ने हमें बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है या इसे जानना-समझना बहुत कठिन लगता है।

"यदि वे खरीद एजेंसियों के साथ मौजूदा संबंधों या सरकारी खरीद के अपने पिछले अनुभव के माध्यम से पहले से ही 'इन-क्राउड' का हिस्सा न हों, तो उनके पास खरीद के अवसरों के बारे में कम जागरुकता है।

"ये उन बाधाओं में शामिल हैं जिनके बारे में हमें सुनाई दिया है तथा हमारे मुद्दे पत्र का उद्देश्य और भी अधिक अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है, अब जबकि हमें इस बारे में सुनाई दे रहा है कि छोटे व्यवसाय और व्यक्ति-विशेष खरीद के लिए सरकार से संपर्क करते समय उनके सामने आने वाली चुनौतियों या कठिनाइयों के बारे में क्या कहते हैं और कहाँ सुधार किए जा सकते हैं।

"इसी के समरूप हम आदर्श एजेंसियों या प्रभावी प्रक्रियाओं अथवा दृष्टिकोणों के उदाहरणों के बारे में, और हम ये 'बेहतर प्रथाएँ' सरकार में अधिक व्यापक रूप से कैसे विस्तारित कर सकते हैं, इस बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं।

MEDIA RELEASE

श्री बिल्सन ने कहा कि वे खरीद प्रणाली का उपयोग करने वालों या ऐसे लोगों से और अधिक प्रतिक्रिया तथा विचार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं।

"किसी छोटे व्यवसाय के लिए सरकारी अनुबंध प्राप्त कर पाना जीवन-परिवर्तक हो सकता है। जैसा कि सभी व्यवसाय जानते हैं, अच्छे ग्राहकों के कोई विकल्प नहीं होते है," श्री बिल्सन ने कहा।

"हमारे सामने प्रदर्शित की गई सबसे बड़ी हताशा अनुबंध जारी करने के लिए सरकारी पैनलों के उपयोग से संबंधित है। पैनल प्रदाताओं की एक छोटी सूची होते हैं, जिसमें से एक विशेष मूल्य तक काम करने के लिए विभाग चयन कर सकता है।

"फिर भी पैनल में शामिल होना काम की गारंटी नहीं देता है। कई छोटे व्यवसायों ने हमें बताया है कि वे कई वर्षों से पैनलों में शामिल हैं और कीमत व्यक्त करने के अनुरोध के लिए उनसे कभी भी संपर्क नहीं किया गया है।

"छोटे व्यवसाय निविदा के लिए आवश्यक समय की अत्यधिक मात्रा और निवेश, तथा एजेंसियों द्वारा इसके विकल्प की लागतों पर विचार किए जाने की कमी की ओर संकेत भी करते हैं।

"निविदा के असफल होने पर सीमित या कोई प्रतिक्रिया न मिलने के प्रावधान से भी घबराहट और झुंझलाहट होती है।

श्री बिल्सन ने यह भी कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए एक गंभीर बाधा कुछ प्रकार के महंगे बीमा की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें बस काम करने का अवसर ही मिल पाए - बिना किसी गारंटी के।

"हम राष्ट्रमंडल खरीद नियमों को देख रहे हैं कि उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है, कौन से विभाग अच्छा काम कर रहे हैं और प्रणाली में सुधार के लिए क्या आगे के कदम भी उठाए जा सकते हैं," उन्होंने कहा।

एएसबीएफईओ की वेबसाइट www.asbfeo.gov.au/procurement पर मुद्दे पत्र और विचारार्थ विषय उपलब्ध हैं, जहाँ प्रस्तुतियाँ भी जमा की जा सकती हैं। प्रस्तुतियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

श्री बिल्सन की रिपोर्ट दिसंबर में सरकार को सौंप दी जाएगी।

मीडिया संपर्क: 0448 467 178